EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By: - Aarav Anand

Date: 07 Dec 2025

Source:- जनसत्ता

भारत व अमेरिका में व्यापार वार्ता 10 से

समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं दोनों देश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

भारत और अमेरिका अपने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर 10 दिसंबर से तीन दिवसीय वार्ता शुरू करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, यह यात्रा महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और अमेरिका इस समय समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं।

सूत्रों ने कहा, 'तीन दिवसीय यह वार्ता 10 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर को समाप्त होगी, और यह औपचारिक दौर की वार्ता नहीं है।' अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) रिक स्वित्जर करेंगे। अगस्त में भारतीय उत्पादों पर 50 फीसद सीमा शुल्क लगाए जाने के अमेरिकी कदम के बाद व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी दल दूसरी बार भारत आ रहा है। इसके

पहले 16 सितंबर को एक अमेरिकी दल भारत के दौरे पर आया था।

अमेरिकी अधिकारियों की वह यात्रा महत्त्वपूर्ण रही। अमेरिकी अधिकारियों की यात्रा रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय माल पर 25 फीसद शुल्क और अतिरिक्त 25 फीसद जुर्माना लगाए जाने के बाद दूसरी यात्रा थी। इससे पहले टीम ने 16 सितंबर को दौरा किया था। 22 सितंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी व्यापार वार्ता के लिए एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए अमेरिका का दौरा किया। उनके साथ मंत्रालय में तत्कालीन विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और अन्य अधिकारी भी थे।

भारत और अमेरिका दो समानांतर वार्ताएं कर रहे हैं – एक शुल्क से निपटने के लिए रूपरेखा व्यापार समझौते पर और दूसरी व्यापक व्यापार समझौते पर। फरवरी में दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने का निर्देश दिया था।

समझौते के पहले चरण को लेकर अब तक छह दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डालर से दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचाना है।

आंकड़े

पांच वर्षों में बिजली की मांग 1056 मेगावाट बढ़ी

सर्दी के आगाज के साथ बिजली की खपत में रेकार्ड बढ़ोतरी

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

राजधानी दिल्ली में अब सर्दियां भी बिजली की रेकार्ड खपत की वजह बनती जा रही हैं। केवल गर्मियों में ही नहीं, बल्कि ठंड के मौसम में भी बिजली की मांग साल-दर-साल बढ़ रही है।

पिछले वर्ष 2024 की भीषण गर्मी में जहां 19 जून को 8656 मेगावाट की ऐतिहासिक अधिकतम मांग दर्ज की गई थी। वहीं सर्दियों में भी खपत लगातार ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में सर्दी के मौसम में बिजली की मांग लगभग 1056 मेगावाट बढ़ी है। राजधानी में बिजली वितरण करने वाली कंपनियां बीएसईएस और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन

टीपीडीडीएल के अनुसार, उत्तरी और बाहरी दिल्ली में इस सर्दी बिजली की अधिकतम मांग 1859 मेगावाट तक पहुंच सकती है। वहीं बीएसईएस द्वारा संचालित दो कंपनियां दिल्ली के अन्य हिस्सों में बिजली की आपूर्ति करती हैं, जहां पर मांग 3920 मेगावाट तक जाने की संभावना है।

लिमिटेड (टीपीडीडीएल) का कहना है कि इस बार सर्दियों के दौरान बिजली की खपत 6000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। पिछले साल इसी मौसम में यह मांग 5655 मेगावाट दर्ज की गई थी। कंपनियों का दावा है कि चाहे मांग 6000 मेगावाट तक भी पहुंच जाए, उन्होंने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर ली है। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 नवंबर 2020 को दिल्ली की बिजली खपत 3430 मेगावाट थी, जो इस वर्ष बढ़कर 4486 मेगावाट तक पहुंच गई। इसके अलावा, 28 नवंबर 2021 को 3494 मेगावाट, 2022 में 3692 मेगावाट, 2023 में 3825 मेगावाट और 2024 में 3856 मेगावाट खपत दर्ज की गई थी। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सर्दियों में बिजली की मांग हर वर्ष स्थिर रूप से बढ़ रही है।

दूसरी ओर, 20 से 27 नवंबर के बीच भी खपत में खासा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इस अवधि में बिजली की मांग 4027 मेगावाट से लेकर 4352 मेगावाट के बीच दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही शहर के लोग हीटर, गीजर और कई घरों में गर्म एवं ठंडे दोनों मौसम में काम करने वाले एसी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिससे बिजली की मांग तेजी से ऊपर जाती है।

अमित शाह ने कहा, चक्रीय अर्थव्यवस्था से पांच साल में

डेयरी किसानों की आय 20 फीसद बढ़ जाएगी

सणादर, 6 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को विश्वास जताया कि देश भर में चक्रीय अर्थव्यवस्था माडल के कार्यान्वयन से अगले पांच वर्षों में डेयरी किसानों की आय में 20 फीसद वृद्धि होगी।

शाह ने यह बात गुजरात के वाव-थराद जिले के सणादर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कही, जो डेयरी के जैव-सीएनजी और उर्वरक संयंत्र के उद्घाटन और दूध पाउडर संयंत्र के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित किया गया था। उन्होंने इस अवसर पर बनास डेयरी से जुड़े पशुपालकों को संबोधित किया। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सफल माडल को विकसित करने के लिए बनास डेयरी के प्रबंधन की सराहना की। इस माडल में किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के कई उपाय शामिल हैं, जैसे कि मवेशियों के गोबर को बायोगैस और जैव-उर्वरक में परिवर्तित करना।

चक्रीय अर्थव्यवस्था में चीजों को इस्तेमाल करके फेंकने की बजाय उनकी मरम्मत, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पर जोर दिया जाता है, जिससे कचरा और प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। शाह ने बताया कि बनास डेयरी के चक्रीय अर्थव्यवस्था माडल को समझने के लिए कई सांसद बनासकांठा आए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हमारी सहकारी डेयरियों को किसानों से दूध खरीदने और दूध उत्पादों को बेचने से होने वाली आय किसानों तक पहुंचाने में बड़ी सफलता मिली है। अब चक्रीय

अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। इसके तहत किसानों से खरीदे गए मवेशियों के गोबर से उत्पादित बायोगैस और उर्वरक बेचकर डेयरी द्वारा उत्पन्न आय में किसानों को उनका हिस्सा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि पूरे देश में इस चक्रीय अर्थव्यवस्था माडल को लागू करने की ठोस योजना शाम को बनासकांठा में सांसदों की बैठक में सामने आएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि जनवरी 2026 में सभी प्रमुख सहकारी डेयरियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डेयरी द्वारा की गई पहलों को समझने के लिए बनास डेयरी का दौरा करेंगे। शाह ने कहा कि पनीर और दही जैसे सामान्य दूध उत्पादों के अलावा, ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी दुनिया भर में मांग है, लेकिन उनका उत्पादन भारत में नहीं होता।

अगर हम इन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करें, तो डेयरी किसान अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए तीन और डेयरी क्षेत्र के लिए तीन सहकारी समितियां बनाई हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था अगले पांच वर्षों में डेयरी किसानों की आय में 20 फीसद की वृद्धि करेगी।

वर्ष 2023 में दो साल से अधिक से 10,566 पाक्सो के मामले लंबित | चिंताजनक | कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को दी जानकारी

उत्तर प्रदेश में इस साल पाक्सो के सर्वाधिक मामले दर्ज

सुशील राघव
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

इस वर्ष यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 19,039 मामले दर्ज किए गए जो इस वर्ष दर्ज मामलों का करीब एक चौथाई है। इतना ही सबसे अधिक पाक्सो अधिनियम के मामले उत्तर प्रदेश में ही लंबित हैं। वर्ष 2025 में पाक्सो अधिनियम के तहत 80,320 मामले दर्ज किए गए।

कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मेघवाल ने निचले सदन के सामने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध पास्को अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को प्रदेशवार प्रस्तुत किया। आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष पाक्सो अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 19,039 मामले दर्ज किए गए जो इस वर्ष दर्ज मामलों का करीब एक चौथाई है। 11,714 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे से स्थान पर रहा। तमिलनाडु में 8,946 मामले, गुजरात में 4,557 मामले और मध्य प्रदेश में 3,973 मामले दर्ज किए गए। अगर अदालतों में लंबित मामलों में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। वर्ष 2023 से यहां पर 10,566 पाक्सो अधिनियम के मामले लंबित हैं।

कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मेघवाल ने निचले सदन के सामने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध पास्को अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को प्रदेशवार प्रस्तुत किया। आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष पाक्सो अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 19,039 मामले दर्ज किए गए जो इस वर्ष दर्ज मामलों का करीब एक चौथाई है। 11,714 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे से स्थान पर रहा। तमिलनाडु में 8,946 मामले, गुजरात में 4,557 मामले और मध्य प्रदेश में 3,973 मामले दर्ज किए गए। अगर अदालतों में लंबित मामलों में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। वर्ष 2023 से यहां पर 10,566 पाक्सो अधिनियम के मामले लंबित हैं।

महाराष्ट्र में दो साल से अधिक लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2023 में 7,962 थी। इसी तरह तमिलनाडु में 1,910 मामले, मध्य प्रदेश में 1,736, असम में 1,693, तेलंगाना में 1,653 और बिहार में 1,079 मामले दो वर्षों से लंबित हैं। देश में 2023 में दो वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या 35,434 थी। लंबित मामलों की संख्या में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। लंबित मामलों की संख्या 2022 में 27,303, 2021 में 18,209, 2020 में 13,572, 2019 में 11,047, 2018 में 7,089, 2017 में 4,395, 2016 में 3,206 और 2015 में 189 मामले लंबित थे। यानी वर्ष 2015 से 2023 तक लंबित मामलों की संख्या में 187 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में पाक्सो अधिनियम के तहत 80,320 मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़े दो दिसंबर तक हैं। अगर पिछले वर्षों की बात करें तो 2024 में 1,22,500, 2023 में 1,19,016, 2022 में 1,11,357 और 2021 में 95,238 मामले पाक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मामलों की संख्या में एक तिहाई से अधिक की कमी दर्ज की गई है। मंत्री की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में 2025 ऐसा वर्ष रहा है जब दर्ज मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों की संख्या से कम रही है। वर्ष 2025 में अब तक कुल 87,854 मामलों को निपटाया गया है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा

भारत व रूस की साझेदारी 70-80 वर्षों में सबसे स्थिर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत-रूस साझेदारी 70-80 वर्षों में 'सबसे स्थिर और अहम संबंधों' में से एक रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा का उद्देश्य आर्थिक सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इन संबंधों को 'फिर से परिभाषित' करना था। जयशंकर ने इस विचार से असहमति जताई कि पुतिन की यात्रा भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी वार्ताओं को जटिल बना सकती है।

जयशंकर ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि नहीं, मैं आपसे असहमत हूं। मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि भारत के दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ बेहतर संबंध हैं। जयशंकर से पूछा गया था कि क्या पुतिन की नई दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा का प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ वार्ता पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि किसी भी देश की ऐसी अपेक्षा उचित नहीं है कि उसे यह कहने या दखल देने का हक है कि हमारे दूसरे देशों के साथ रिश्ते कैसे हों। क्योंकि याद रखिए, दूसरे देश भी वही अपेक्षा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमने हमेशा स्पष्ट किया है कि हमारे अनेक देशों के साथ संबंध हैं। हमारे पास अपनी पसंद की आजादी है। हम जिसे रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं, उसके बारे में लगातार बात करते रहे हैं और वह जारी भी है। मुझे समझ नहीं आता कि किसी के पास इसके विपरीत अपेक्षा करने का कोई कारण क्यों होना चाहिए।

फाइल फोटो

जयशंकर ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि नहीं, मैं आपसे असहमत हूं। मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि भारत के दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ बेहतर संबंध हैं। जयशंकर से पूछा गया था कि क्या पुतिन की नई दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा का प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ वार्ता पर असर पड़ेगा।

विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि ट्रंप प्रशासन का ध्यान व्यापार पर रहा है और कहा कि इस दिशा में भारत का दृष्टिकोण पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय व्यापार सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। यह स्पष्ट रूप से वाशिंगटन की सोच का केंद्र बिंदु है, यह पहले की सरकारों की तुलना में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसे हमने पहचाना है और हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन हम उचित शर्तों पर इसका सामना करने के लिए तैयार हैं।

'इंडिगो उड़ान व्यवधान मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

विमानन नियामक डीजीसीए ने शनिवार को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर उड़ानों में भारी व्यवधान के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। वहीं, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के मामले में जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे। लगातार पांचवें दिन उड़ानों में व्यवधान जारी रहने के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स के साथ स्थिति की समीक्षा करने और मुद्दों का समाधान करने के लिए एक अहम बैठक की। दिल्ली में हुई और इस बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा और डीजीसीए प्रमुख फैज अहमद किदवई सहित अन्य लोग शामिल हुए। डीजीसीए ने स्थिति के कारणों का पता लगाने और राहत उपायों की सिफारिश करने के लिए चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।

नियामक ने कहा कि बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताएं योजना में खामियों का संकेत देती हैं। सीईओ के रूप में आप एअरलाइन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं।

इजराइल की रक्षा कंपनी ने कहा

भारत को 40 हजार एलएमजी की पहली खेप जल्द

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

इजराइल की एक प्रमुख रक्षा कंपनी ने बताया कि उसकी योजना अगले साल की शुरुआत में भारत को 40,000 लाइट मशीन गन (एलएमजी) की पहली खेप की आपूर्ति करने की है। साथ ही लगभग 1,70,000 नए जमाने की कार्बाइन (एक प्रकार की बंदूक) की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर से जुड़ी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

'इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज' (आइडब्लूआइ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शुकी श्वार्ट्ज ने यह भी बताया कि उनकी कंपनी वर्तमान में भारत के गृह मंत्रालय की विभिन्न एजंसियों के साथ मिलकर पिस्तौल, राइफल और मशीन गन सहित उनके उत्पादों का विपणन कर रही है।

श्वार्ट्ज ने एक साक्षात्कार में कहा कि हम अभी तीन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हैं। पहला, 40,000 लाइट मशीन गन का अनुबंध, जिस पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे। हमने सभी परीक्षण और सरकारी जांच पूरी कर ली है तथा हमें उत्पादन का लाइसेंस मिल गया है। हमारा इरादा साल की शुरुआत में पहली खेप की आपूर्ति करने का है।

उन्होंने आपूर्ति की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि एलएमजी की आपूर्ति पांच साल के लिए है। हम इसे और भी जल्दी दे सकते हैं लेकिन पहली आपूर्ति साल की शुरुआत में होगी। दूसरे कार्यक्रम में सीक्यूबी (क्लोज क्वार्टर्स बैटल) कार्बाइन निविदा शामिल है, जहां कंपनी दूसरी बोलीदाता थी। 'भारत फोर्ज' प्राथमिक बोलीदाता है। उन्होंने बताया कि हमारा इरादा अनुबंध का 40 फीसद आपूर्ति करने का है। हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हैं और मेरा मानना है कि इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 'सीक्यूबी कार्बाइन' की आपूर्ति का 60 फीसद 'भारत फोर्ज' करेगा जबकि शेष 40 फीसद (170,000 इकाइयां) अदाणी समूह की सहायक कंपनी पीएलआर सिस्टम्स द्वारा वितरित की जाएंगी। उन्होंने 'पीएलआर सिस्टम्स' के माध्यम से अडाणी समूह के साथ मजबूत साझेदारी पर प्रकाश डाला।

आइडब्लूआइ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि हमारा इरादा अनुबंध का 40 फीसद आपूर्ति करने का है। हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हैं और मेरा मानना है कि इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 'सीक्यूबी कार्बाइन' की आपूर्ति का 60 फीसद 'भारत फोर्ज' करेगा जबकि शेष 40 फीसद (170,000 इकाइयां) अदाणी समूह की सहायक कंपनी पीएलआर सिस्टम्स द्वारा वितरित की जाएंगी। उन्होंने 'पीएलआर सिस्टम्स' के माध्यम से अडाणी समूह के साथ मजबूत साझेदारी पर प्रकाश डाला।

श्वार्ट्ज ने एक साक्षात्कार में कहा कि हम अभी तीन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हैं। पहला, 40,000 लाइट मशीन गन का अनुबंध, जिस पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे। हमने सभी परीक्षण और सरकारी जांच पूरी कर ली है तथा हमें उत्पादन का लाइसेंस मिल गया है। हमारा इरादा साल की शुरुआत में पहली खेप की आपूर्ति करने का है।

उन्होंने आपूर्ति की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि एलएमजी की आपूर्ति पांच साल के लिए है। हम इसे और भी जल्दी दे सकते हैं लेकिन पहली आपूर्ति साल की शुरुआत में होगी। दूसरे कार्यक्रम में सीक्यूबी (क्लोज क्वार्टर्स बैटल) कार्बाइन निविदा शामिल है, जहां कंपनी दूसरी बोलीदाता थी। 'भारत फोर्ज' प्राथमिक बोलीदाता है। उन्होंने बताया कि हमारा इरादा अनुबंध का 40 फीसद आपूर्ति करने का है। हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हैं और मेरा मानना है कि इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 'सीक्यूबी कार्बाइन' की आपूर्ति का 60 फीसद 'भारत फोर्ज' करेगा जबकि शेष 40 फीसद (170,000 इकाइयां) अदाणी समूह की सहायक कंपनी पीएलआर सिस्टम्स द्वारा वितरित की जाएंगी। उन्होंने 'पीएलआर सिस्टम्स' के माध्यम से अडाणी समूह के साथ एक मजबूत साझेदारी पर भी प्रकाश डाला, जो हल्के हथियारों के निर्माण और स्थानीय स्तर पर आर्वेल प्रणालियों के एकीकरण पर केंद्रित है। श्वार्ट्ज ने यूरोपीय देशों द्वारा कुछ उपकरणों की आपूर्ति पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस कारण से इजराइल को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की आवश्यकता है और वैश्विक स्तर पर रक्षा बलों का समर्थन करने के लिए हमारी अपनी आपूर्ति शृंखला है।

गुमशुदा घुसपैठिए

केंद्रीय चुनाव आयोग के विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण से ज्वलंत हुआ मुद्दा
बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल पर बहस
उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक की सरकारें दिखा रही हैं कड़ा रुख

केंद्रीय चुनाव आयोग के विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण की कवायद शुरू होने के बाद बिहार में घुसपैठियों का मामला उठा। अब बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में यह कवायद चल रही है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का मसला फिर से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का रूप ले चुका है। पुनरीक्षण में बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, अभी तक इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मसले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की-क्या घुसपैठियों का स्वागत लाल कालीन बिछाकर किया जाए? इन कवायदों के बीच अहम यह है कि घुसपैठिए राजनीतिक गणना में तो हैं, लेकिन आंकड़ों में खोजें तो जमीन पर गुम हैं।

जनसत्ता सरोकार

बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के जरिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करने का जो मुद्दा उठा था, वह तब हाशिए पर चला गया, जब चुनाव आयोग यह नहीं बता पाया कि इस कवायद में कितने बांग्लादेशी मतदाता मिले। लेकिन चुनाव हुए कुछ ही दिन बीते थे कि देश के 12 राज्यों में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया और पश्चिम बंगाल इसका केंद्रबिंदु बन गया। खबरें आईं कि बंगाल से बहुत से बांग्लादेशी, जिनका मौजूदा मतदाता सूची में नाम है, उनका हुजूम भारत-बांग्लादेश सीमा पर उमड़ पड़ा है और वे अपने देश वापस जाना चाहते हैं।

इस बीच, घुसपैठियों का मामला उस समय तूल पकड़ गया जब 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि बांग्लादेशियों की पहचान के लिए व्यापक अभियान चालू किया जाए और उन्हें निरुद्ध केंद्रों में भेज दिया जाए। पुनरीक्षण से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश तक को विपक्ष ने सत्ता पक्ष का चुनावी लाभ उठाने का कदम करार दिया। उसने कहा कि अगर घुसपैठिए मौजूद हैं तो यह मौजूदा सरकारों की नाकामी है। वहीं केंद्र व राज्य में मौजूद सत्ता पक्ष ने इन कवायदों को जायज ठहराया है।

उप्र सरकार के आदेश पर मचे घमासान के दौरान ही मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुद्दे पर अपनी राय जताकर घुसपैठ के मुद्दे को नया आयाम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने रोहिंग्या मुद्दे पर एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या घुसपैठियों का स्वागत लाल कालीन बिछाकर किया जाए? इस याचिका में आरोप लगाया गया

भारत में रोहिंग्या

यूएनएचसीआर पंजीकृत 16,000
सरकारी अनुमान 40,000
दिल्ली में संख्या 1100

अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई

(एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक)

वापस भेजे गए
2,331

बांग्लादेशी नागरिक
411

नाइजीरियाई नागरिक
1470

युगांडा के नागरिक
78

कहां कितने निरुद्ध केंद्र

राजस्थान – झाड़ोल, उदयपुर, मोड़ता, नागौर, बहरोड़

ओड़ीशा 20 – राज्यस्तर पर दो, जिलास्तर पर 18

केरल –साल 2022 में पहला ट्रांजिट होम शुरू किया गया

कर्नाटक– दो निरुद्ध केंद्र , एक बंगलुरु के पास नेलमंगला में है

महाराष्ट्र – जुलाई 2024 में नवी मुंबई में स्थायी निरुद्ध केंद्र बनाने को मंजूरी

असम– छह निरुद्ध केंद्र – डिब्रूगढ़, गोलपारा, जोरहाट, कोकराझार, सिल्चर, तेजपुर

दिल्ली– सेवा सदन शहजादा बाग, लामपुर सेवा सदन

भारत के लिए चुनौती बना म्यांमा का रोहिंग्या संकट

म्यांमा में रोहिंग्या संकट एक और आयाम प्रस्तुत करता है। म्यांमा के रखाइन प्रांत में सताए गए राज्यविहीन मुसलिम अल्पसंख्यक के रूप में, कई रोहिंग्या भारत भाग आए हैं। ये लोग बांग्लादेश से होते हुए भारत पहुंचे हैं। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने अगस्त 2017 में राज्यसभा को सूचित किया था कि भारत में अवैध रोहिंग्याओं की आबादी 40,000 से अधिक हो गई है। अनुमान है कि लगभग 75,000 अवैध रोहिंग्या प्रवासी वर्तमान में भारत में रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 22,000 नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) कार्यालय में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हैं।

जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में रोहिंग्याओं की आवाजाही गंभीर सुरक्षा चिंताओं को जन्म देती है। इसके अलावा, उनके कट्टरपंथी बनने की संभावना भी बनी हुई है, खासकर जब से आइएस और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों ने उनकी दुर्दशा का फायदा उठाने में रुचि दिखाई है। चूंकि ज्यादातर रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते आए हैं, इसलिए भारत उनका पहला शरणस्थल नहीं है। इस आधार पर उन्हें शरण देने का कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व शायद भारत पर न हो।

Source:- दैनिक जागरण

इंडिगो के मनमानेपन पर सरकार सख्त, तय की किराये की सीमा

इंडिगो को आज शाम आठ बजे तक देना होगा रिफंड, 48 घंटे में पहुंचाना होगा लगेज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- घरेलू उड़ानों के लिए अधिकतम 18000 रुपये तक होगा किराया
- बिजनेस क्लास या उड़ान स्कीम पर लागू नहीं होगी किराये की सीमा

दूरी	किराया (रुपये में)
500 किमी तक	7500
501-1000 किमी	12000
1001-1500 किमी	15000
1500 किमी से ऊपर	18000

स्थिति सामान्य होने तक इकोनमी क्लास के लिए यह किराया लागू रहेगा।

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली के टर्मिनल 1 पर शनिवार को इंडिगो एयरलाइन के काउंटर पर इंतजार कर रहे यात्री। पीटीआई

पांच दिनों तक इंडिगो द्वारा मनमाने तरीके से हजारों उड़ानें रद करने, लाखों यात्रियों को बेसहारा छोड़ने और ऐसी स्थिति में लाभ कमाने के लिए विमानन कंपनियों की ओर से घरेलू किराये की आसमान पर पहुंचाने के बाद शनिवार को आखिरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय सख्त कार्रवाई करता दिखा।

मंत्रालय ने शनिवार को घरेलू उड़ानों के इकोनमी क्लास किराये पर तत्काल प्रभाव से ऊपरी सीमा (कैप) लगा दी। दूरी के हिसाब से अब किराया 7500 रुपये से 18000 रुपये तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही इस अव्यवस्था की जिम्मेदार कंपनी इंडिगो को कड़ा निर्देश दिया गया है कि रद उड़ानों का पूरा रिफंड रविवार शाम आठ बजे तक पूरा किया जाए। यात्रियों का लगेज 48 घंटे में उन तक पहुंचाया जाए। हालांकि, सरकार के स्तर पर इन कोशिशों से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की वजह से भारत के विमानन क्षेत्र की विश्वसनीयता को जो गहरा आघात पहुंचाया है, उसकी जल्द भरपाई होनी मुश्किल है। दुनिया के सामने भारतीय उड्डयन उद्योग ने ऐसी छवि पेश की है, जहां उपभोक्ता अधिकार व यात्री सुरक्षा प्राथमिकता में सबसे नीचे हैं।

पांच दिन से जारी इंडिगो संकट के बाद बाकी एयरलाइंस ने किराये आसमान पर पहुंचा दिए। हालत यह थी कि शुक्रवार को कोलकाता-मुंबई का बन-वे टिकट कोलकाता-लंदन से ज्यादा था। मुंबई-भुवनेश्वर का टिकट 84000 रुपये तक पहुंच गया था। आसमान छूते किराये के बाद सरकार हरकत में आई और इसकी सीमा तय कर दी। यह सीमा बिजनेस क्लास या उड़ान स्कीम के तहत लागू किराये के लिए नहीं है। दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-बेंगलुरु, मुंबई-कोलकाता जैसे ज्यादातर प्रमुख रूट अब किराए अधिकतम 18000 रुपये तक ही रहेंगे। यह कैप तब तक लागू रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा, इस निर्देश का उद्देश्य बाजार में मूल्य-अनुशासन बनाए रखना, संकट में फंसे यात्रियों का किसी भी रूप में शोषण रोकना तथा यह सुनिश्चित करना है कि तत्काल यात्रा करने की जरूरत वाले नागरिकों को इस दौरान आर्थिक कष्ट न झेलना पड़े।

मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों से री-शेड्यूलिंग या री-बुकिंग का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इंडिगो को विशेष यात्री सहायता और रिफंड सेल स्थापित करना होगा, जो स्वयं यात्रियों से संपर्क कर रिफंड और वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, मरीज, छात्र आदि को प्राथमिकता के साथ सहायता देनी होगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वह सभी एयरलाइंस और आनलाइन ट्रैवल पोर्टलों पर रियल-टाइम किराया निगरानी कर रहा है। निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई होगी।

इंडियन एसोसिएशन आफ टूर आपरेटर्स व फेडरेशन आफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हास्पीटिलिटी ने हवाई किराये की सीमा तय करने का स्वागत किया। कहा,अनियंत्रित किराया वृद्धि से उपभोक्ता विश्वास को ठेस पहुंचती है। उन्होंने स्थायी नीति, बेहतर आपात योजना व किराया निगरानी की मांग की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि वह सभी हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है।

(पेज-5 भी देखें)

इंडिगो ने पांचवें दिन भी रद की 800 से अधिक उड़ानें

- दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से शनिवार को 106 उड़ानें रद हुईं
- इंडिगो ने कहा, 95 प्रतिशत से अधिक नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल
- एक दिन पूर्व की तुलना में स्थिति सुधरी 1500 उड़ानों का किया संचालन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

इंडिगो की शनिवार को लगातार पांचवें दिन 800 से अधिक उड़ानें रद होने से यात्री हलकान रहे। कंपनी ने एक दिन पहले 1600 उड़ानें रद की थीं। देश के विमानन इतिहास में किसी भी भारतीय एयरलाइन द्वारा एक दिन में उड़ानें रद करने का यह रिकार्ड है। इंडिगो सामान्य रूप से प्रतिदिन 2300 उड़ानें संचालित करती है। एयरलाइन ने कहा, उसने शनिवार को 1500 उड़ानें संचालित कीं। यह भी कहा, 95 प्रतिशत से अधिक नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है, क्योंकि मौजूदा 138 गंतव्यों में से 135 पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है।

घरेलू विमानन सेवा में इंडिगो की 64 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसलिए उड़ानें थमने से हजारों यात्री विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से शनिवार को 106 उड़ानें रद हुईं। कलकत्ता हवाई अड्डे पर 41 उड़ानें रद की गईं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा, देशभर के हवाई अड्डों पर यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। चेक-इन व चेक-आउट सुचारु रूप से हो रहा है।

मनमाने तौर-तरीके और गैरपेशेवर व्यवहार का आरोप झेल रही इंडिगो ने एक्स व अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि उड़ानें रद या देरी होने का मुख्य कारण अचानक बड़ी संख्या में स्टाफ की अनुपस्थिति, क्रू की उपलब्धता में कमी, आपरेशनल मैनेजमेंट व सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन में गड़बड़ी है। एक क्रू मेंबर के सीक्वेंसिंग में फंसने से कई उड़ानें रद करनी पड़ीं। इंडिगो अपने परिचालन को पटरी पर लाने के लिए काम कर रही है। हमारी टीमें शेड्यूल को स्थिर करने और देरी को कम करने पर लगी हुई हैं।

भारतीय विमानन परिषद ने की जांच की मांग पेज>>5

सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है, देना चाहता हूं कड़ा संदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र: चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए होने का कड़ा संदेश देते हुए कहा,, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए तय समयसीमा व एकीकृत राष्ट्रीय न्यायिक नीति उनकी प्राथमिकता होगी। एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में उन्होंने न्याय तक पहुंच का उल्लेख करते हुए कहा, उनकी प्राथमिकता मुकदमेबाजी की लागत को कम करना और मामलों के निर्णय के लिए उचित समय-सीमा निर्धारित करना है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर पूछे गए सवाल के जवाब में सीजेआइ ने शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संविधान ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है ताकि कोई भी एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। तीनों अंग एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए हुए हैं।

सीजेआइ सूर्यकांत। फाइल

लोकतंत्र व न्याय प्रणाली का भविष्य उज्ज्वल

चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां तक न्याय में समयसीमा का सवाल है तो जिला न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रदान करने की प्रणाली दोनों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। उन्होंने कहा- "कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला, भारतीय लोग संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, भारतीय कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं और तीसरा, भारतीय लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं।"

चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पुराने मामलों का निपटारा आवश्यक है और इसके लिए मध्यस्थता को प्रभावी उपाय के रूप में अपनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में सुधारों की बात करते हुए कहा कि कुछ मुकदमों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा- "मैं एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है और किसी भी सामान्य वादी को शीर्ष अदालत में पर्याप्त स्थान और समय मिलेगा। इसके लिए, मैं सूचीबद्ध किए जाने वाले मामलों की प्राथमिकता तय कर रहा हूं।" साथ ही उन्होंने कहा कि वह यह काम अकेले नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने इस संबंध में अपना पूरा सहयोग दिया है।

सीजेआइ ने माना कि न्यायिक प्रणाली को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों का हवाला दिया। उन्होंने कहा-" नई चुनौतियां आती रहेंगी। सबसे पहले, हमें अपनी न्यायपालिका को अपडेट करने की आवश्यकता है। हमें अपने न्यायिक अधिकारियों को नई चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में तैयार करना होगा।"

हाशिए पर पड़े समुदायों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए: सीजेआइ ने न्यायपालिका में विविधता पर कहा कि जिस तरह से समाज विकसित हुआ है और जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, उसमें भारतीय न्यायिक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि समुदायिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अब विभिन्न क्षेत्रों से न्यायाधीशों को लाने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हमने हमेशा यह प्रयास किया है कि हाशिए पर पड़े समुदायों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि मध्यस्थता एक बहुत प्रभावी साधन साबित हो रही है तथा दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है।

नवंबर में 10 सबसे प्रदूषित शहरों में आठ एनसीआर के

चिंताजनक ▶ गाजियाबाद सबसे जहरीला, नोएडा दूसरे, बहादुरगढ़ तीसरे व दिल्ली चौथे स्थान पर, ग्रेटर नोएडा की हवा खराब

सीआरईए की मासिक रिपोर्ट के अनुसार वाहनों की भीड़, धूल और अन्य स्थानीय कारक जिम्मेदार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की मासिक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से आठ एनसीआर के हैं। इनमें सबसे खराब हवा गाजियाबाद की रही, उसके बाद नोएडा रहा। पिछले साल की तुलना में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार है, लेकिन अन्य नौ शहरों की हवा इस बार पिछले नवंबर की तुलना में अधिक खराब रही।

सीआरईए ने वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से प्राप्त पीएम 2.5 के आंकड़ों के आधार पर नवंबर माह की रिपोर्ट जारी की है। इसमें गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां पीएम 2.5 का औसत मासिक स्तर 224 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु गुणवत्ता मानक (एनएक्यूएस) के निर्धारित 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बहुत अधिक है। शहर में 19 दिन 'बहुत खराब', 10 दिन 'गंभीर' और एक दिन 'खराब' श्रेणी की वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। नोएडा, बहादुरगढ़, दिल्ली, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, बागपत, सोनीपत, मेरठ और रोहतक भी शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में शामिल रहे। बहादुरगढ़ को छोड़कर इनमें से किसी भी शहर में एक भी दिन एनएक्यूएस मानक के भीतर वायु गुणवत्ता दर्ज नहीं हुई। चरखी दादरी, बुलंदशहर, जींद, मुजफ्फरनगर, गुरुग्राम, खुर्जा, भिवानी, करनाल, यमुनानगर और फरीदाबाद जैसे कई अन्य शहरों में भी पूरे महीने पीएम 2.5 का स्तर मानक से ऊपर रहा।

दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर अक्टूबर की तुलना में दोगुना बढ़ाः नवंबर में दिल्ली का मासिक औसत पीएम 2.5 स्तर 215 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ, जो अक्टूबर में दर्ज 107 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की तुलना में लगभग दोगुना है। पूरे महीने दिल्ली में 23 दिन 'बहुत खराब', छह दिन 'गंभीर' और एक दिन 'खराब' वायु गुणवत्ता वाले रहे।

वाहनों व अन्य स्रोतों से उत्सर्जन में तनी होगी कमीः सीआरईए के विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा कि पराली जलाने में उल्लेखनीय कमी के बावजूद एनसीआर के 29 में से 20 शहरों में पिछले साल की तुलना में प्रदूषण स्तर अधिक रहा।

स्पष्ट है कि वाहनों, औद्योगिक इकाइयों, पावर प्लांट और अन्य दहन स्रोतों से प्रदूषण बढ़ रहा है। जब तक क्षेत्रवार उत्सर्जन में कटौती नहीं होगी, शहरों की हवा नहीं सुधरेगी। इसके लिए लोगों को पहल करनी होगी।

शनिवार को बढ़े प्रदूषण में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मयूर विहार फेस 2 के समीप स्मोग के बीच जाते राहगीर। धंद्र प्रकाश मिश्र

राजस्थान व हरियाणा के ज्यादा शहर प्रदूषित

राज्य स्तर पर राजस्थान में सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहे। यहां 23 शहरों की हवा एनएक्यूएस मानक से अधिक प्रदूषित रही। हरियाणा के 22 और उप्र के 14 शहर भी इसी श्रेणी में रहे। मध्य प्रदेश व ओडिशा के नौ-नौ और पंजाब के सात शहरों में पीएम 2.5 स्तर मानक से ऊपर पाया गया। वहीं, मेघालय की राजधानी शिलांग भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा, जहां मासिक औसत पीएम 2.5 स्तर केवल सात माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ।

प्रदूषण रोकथाम के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और दीर्घकालिक प्रबंधन पर साक्ष्य आधारित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वायु प्रदूषण पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। एक अधिकारी ने कहा कि विशेषज्ञ निकाय का गठन दिल्ली सरकार को विभिन्न मानवजनित और प्राकृतिक कारकों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों, उभरती प्रौद्योगिकियों और नीतिगत सुधारों पर सलाह देने के लिए किया गया है। यह समूह दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रबंधन रणनीति का मार्गदर्शन, मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक उच्च-स्तरीय सलाहकार पैनल के रूप में कार्य करेगा। आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त आइएएस और पूर्व केंद्रीय पर्यावरण सचिव लीना नंदन विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। अन्य सदस्यों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व सदस्य सचिव डा. जेएस कामोत्रा, आइआइटी दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे, आइआइटी कानपुर के प्रोफेसर मुकेश शर्मा, टेरी के सर्कुलर इकोनामी और अपशिष्ट प्रबंधन निदेशक डा. सुनील पांडेय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी), एपीएजी और पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली की हवा

दिल्ली की हवा शनिवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 333 पर पहुंच गया जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। रविवार को हवा चलने से इसमें कुछ कमी आने का अनुमान है। सीपीसीबी के समीर एप के आंकड़ों के अनुसार मुंडका सबसे अधिक प्रदूषण रहा। रात नौ बजे के आंकड़ों के अनुसार यहां एक्यूआइ सबसे खराब 382 दर्ज किया गया। दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रों में से 30 में बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। शेष 10 ने खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की। बहुत खराब वायु गुणवत्ता दर्ज करने वाले स्टेशनों में मुंडका के साथ ही आरके पुरम, पंजाबी बाग, चांदनी चौक, रोहिणी, विवेक विहार, बवाना, वजीरपुर, आनंद विहार, अशोक विहार और सोनिया विहार शामिल हैं। आइआइटीएम-पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार, प्रदूषण में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का स्थानीय स्तर पर बड़ा योगदान 14.8 प्रतिशत रहा। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों का योगदान 7.3 प्रतिशत रहा। आधासीय स्रोतों से 3.6 प्रतिशत, निर्माण धूल से 2 प्रतिशत हुआ।

किशारों के मुकदमे निपटाने में 73.7 की दर के साथ उत्तराखंड आगे

दिल्ली में केसों की निपटान दर 41.9 प्रतिशत, यह राष्ट्रीय औसत से कम, हरियाणा में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत

माला दीक्षित ● जागरण

नई दिल्ली : न्याय की धीमी रफ्तार कानून तोड़ने वाले किशोरों के मुकदमों में भी दिखाई देती है। देशभर में 362 जुवेनाइल जस्टिस बोर्डों में कम से कम 55, 000 केस लंबित हैं और 9,907 किशोर बाल देखरेख संस्थानों में निरुद्ध हैं जिनमें से तीन चौथाई यानी हर चार में से तीन किशोर 16 से 18 साल के हैं। केसों के निपटारे का राष्ट्रीय औसत करीब 45 प्रतिशत है। किशोरों के मुकदमों को निपटाने में मिजोरम अव्वल और उड़ीसा सबसे फिसड्डी है। मिजोरम चूंकि छोटा राज्य है, उस लिहाज से केसों के निपटान की उत्तराखंड की दर 73.7 प्रतिशत है जोकि काफी अच्छी है। हरियाणा और मध्य प्रदेश की यह दर क्रमशः 58 प्रतिशत और 51.4 प्रतिशत है। दिल्ली की बात करें तो यहां केसों की निपटान दर राष्ट्रीय औसत से भी कम 41.9 प्रतिशत है। बड़ी बात ये है उत्तर प्रदेश और बिहार ने अपना डाटा ही साझा नहीं किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुवेनाइल जस्टिस की देशभर में स्थिति देखी जाए तो ढांचागत संसाधनों की कमी है जो क्षमता पर असर डालती है।

प्रतीकात्मक

मध्य प्रदेश में 51.4 प्रतिशत मामले निपटाए गए, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने डाटा ही साझा नहीं किया

किशोर न्याय की स्थिति का आंकलन करने वाली एक हालिया रिपोर्ट से सामने आई जानकारी

निर्धारित बुनियादी ढांचा व कार्यबल तैयार नहीं: वलय

जुवेनाइल जस्टिस के हाल का विश्लेषण करने वाले इंडिया जस्टिस के टीम लीडर वलय सिंह कहते हैं कि ये रिपोर्ट दर्शाती है कि 2015 के जेजे अधिनियम संशोधन के दस साल बाद भी हम कानून द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचा व कार्यबल तैयार नहीं कर पाए हैं। ये उन सभी संस्थाओं की विफलता को दर्शाता है जिनका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। रिपोर्ट ये दर्शाती है कि इनके लिए विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारियों, सेपटी होम और आफ्टरवेशन होम जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की गंभीर कमी है।

यह राजफाश देश में किशोर न्याय क्षमता का आंकलन करने वाली इंडिया जस्टिस की किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे पर आई हालिया रिपोर्ट में हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी), बाल देखरेख संस्थान (सीसीआइ), विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (एसपीजेयू) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) जैसे प्रमुख संस्थानों की क्षमता का विश्लेषण किया गया है। कानून तोड़ने वाले किशोरों के केसों पर अगर नजर डाली जाए तो देशभर में 31,365 केस आइपीसी और अन्य विशेष या स्थानीय कानून में दर्ज हुए। इनमें 40,036 किशोर निरुद्ध किए गए। किशोर बाल देखरेख संस्थानों में निरुद्ध 9,907 किशोरों में से हर चार में से तीन की आयु 16 से 18 वर्ष के बीच है। इसका मतलब है कि परिपक्वता के मुहाने पर खड़े किशोर इस ओर ज्यादा अग्रसर हैं।

देश में कुल 765 जिले हैं और 707 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैं जहां किशोरों के केस चलते हैं। इनमें से 362 बोर्डों ने ही सूचना साझा की है जिसके मुताबिक वहां 55,000 केस लंबित हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों ने सूचना साझा नहीं की। इसलिए उनके आंकड़े शामिल नहीं हैं। रिपोर्ट बताती है कि मामले निपटाने की राष्ट्रीय दर 44.69 प्रतिशत है। अगर दिल्ली को देखा जाए तो यहां केसों की निपटान दर राष्ट्रीय औसत से कम है। हालांकि दिल्ली में प्रति विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी (एलसीपीओ) पर औसतन 820 केसों का भार है जो राज्यों के उपलब्ध आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर 2023 तक देशभर में 362 जुवेनाइल जस्टिस बोर्डों में 55 प्रतिशत केस लंबित थे। केस निपटाने में मिजोरम अव्वल है जहां 79 प्रतिशत मामले निपटाए गए। मिजोरम छोटा राज्य है, उस लिहाज से उत्तराखंड की 73.7 प्रतिशत की दर अच्छी है जबकि उड़ीसा में यह दर सबसे खराब 17.4 प्रतिशत रही।

लालकिला धमाके के दोषियों को सजा मिले, यूएन सदस्य सहयोग करें : क्वाड

अपील ▶ हिंद-प्रशांत को आतंकमुक्त बनाने को क्वाड देशों की साझा रणनीति पर सहमति

शहरी आतंकवाद-रोधी अभियानों पर टेबलटाप एक्सरसाइज, सूचना साझा करने पर जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया वाले क्वाड समूह ने लालकिले के पास हुए आतंकवादी हमले के दोषियों, साजिशकर्ताओं और फंडिंग नेटवर्क को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में चारों देशों ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वह अपने सभी सदस्य देशों को इस प्रयास में सहयोग के लिए प्रेरित करे।

2023 में गठित इस वर्किंग ग्रुप की यह तीसरी बैठक थी। भारत ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए क्वाड में ठोस और साझा संकल्प की जरूरत है। बैठक के दौरान क्वाड देशों ने आतंकवाद- विशेषकर सीमा पार आतंकवाद- की कड़े शब्दों में निंदा की और 10 नवंबर को लालकिले के पास हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया।

बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते आतंकी खतरों का विस्तृत मूल्यांकन साझा किया गया और क्षेत्र को आतंकमुक्त रखने के लिए एक संयुक्त रणनीति पर काम करने की सहमति बनी। साथ ही उभरते खतरों से निपटने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान ''शहरी वातावरण में आतंकवाद-रोधी अभियानों'' पर टेबलटाप एक्सरसाइज भी आयोजित की गई, जिसमें विशेषज्ञों ने कार्यक्षमता और सर्वोत्तम प्रक्रियाएं साझा कीं। क्वाड देशों ने सहमति जताई कि आतंकियों, आतंकी संगठनों और उनके संरक्षकों पर निरंतर और प्रभावी सूचना साझा करना भविष्य की सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

दिल्ली बम धमाका। फाइल

क्या है क्वाड

क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलाग चार देशों- भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया का रणनीतिक समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और मुक्त व खुला समुद्री क्षेत्र सुनिश्चित करना है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई और 2017 के बाद सक्रियता आई। यह सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि सहयोग मंच है। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच क्वाड को हिंद-प्रशांत में संतुलन व सुरक्षा की पहल माना जाता है।

भारत- अमेरिका ने कहा, लश्कर- जैश और समर्थकों पर यूएन करे अतिरिक्त कार्रवाई

भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके समर्थक नेटवर्क पर संयुक्त राष्ट्र के तहत अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई जैसे वैश्विक संपत्ति जब्ती और हथियार प्रतिबंध की मांग की है। दोनों देशों ने तीन दिसंबर को नई दिल्ली में हुई संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूसी) की बैठक और 'डेजिग्नेशंस डायलाग' में आतंकवाद-रोधी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग को धन्यवाद दिया। दोनों देशों के संयुक्त बयान में कहा गया कि आतंकवाद से निपटने के लिए सतत और सामूहिक कार्रवाई आवश्यक है। दोनों पक्षों ने आइएसआइएस, अल-कायदा और अन्य आतंकी गुटों के खिलाफ भी 'संयुक्त राष्ट्र 1267' प्रतिबंधों के तहत और नाम जोड़ने की मांग की। भारत और अमेरिका ने सभी प्रकार के आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए ड्रोन और एआइ के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई। दोनों देशों ने यूएन, क्वाड और एफएटीएफ में मिलकर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

'हमारे निर्णयों को वीटो का अधिकार किसी को नहीं'

- पुतिन के दौरे के बाद अमेरिका को मोदी सरकार का साफ संदेश
- विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, रूस से भारत के संबंध मजबूत और स्थिर

जयशंकर फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात से असहमति जताई है कि पुतिन के दौरे से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए चल रही वार्ता पर नकारात्मक असर पड़ेगा और वह जटिल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के सभी बड़े देशों से अच्छे संबंध हैं। लेकिन किसी देश को हमें वीटो करने या हमसे यह कहने का अधिकार नहीं है कि हम अन्य देशों के साथ किस तरह के संबंध रखें। यह उचित भी नहीं है।

एक मीडिया समूह के प्रश्नोत्तर सत्र में जयशंकर ने इस बात से असहमति जताई कि पुतिन के दौरे से भारत और अमेरिका के बीच स्थितियां जटिल हो जाएंगी। विदेश मंत्री ने कहा कि हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे बहुत से देशों से प्रगाढ़ संबंध हैं। संप्रभु राष्ट्र के तौर पर हमारे पास मित्रों के चयन की स्वतंत्रता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सफल भारत दौरे के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों को विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत और स्थिर बताया। कहा, दोनों देशों के संबंध पिछले 70-80 वर्षों से हैं और ये निरंतर मजबूत होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन का हाल का नई दिल्ली दौरा सहयोग को नए रूप में विस्तार करने वाला है। इसके तहत अब दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाए जाएंगे।

जयशंकर ने कहा, हम हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता की बात कहते हैं और उस पर आगे बढ़ने की नीति पर कार्य कर रहे हैं। सरकार की इस नीति के विरोध में देश में शायद कोई नहीं है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की नीतियों का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि उसका फोकस व्यापार बढ़ाने की ओर है। भारत भी व्यापार बढ़ाने का पक्षधर है लेकिन इस राह में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। अमेरिका के समक्ष यह बात हम रख चुके हैं। हम सभी के साथ उचित शर्तों और तरीकों से काम करना चाहते हैं। अगर कोई कूटनीति को हथियार बनाकर हमारे निर्णयों को प्रभावित करना चाहे तो उसे सफलता नहीं मिलेगी, उसे निराश ही होना पड़ेगा। जयशंकर ने ये बातें तब कही हैं जब भारत-अमेरिका के रिश्ते पिछले 20 वर्षों में सबसे कमजोर स्थिति में आ गए हैं।

डीपफेक को रेगुलेट करने वाला बिल लोकसभा में पेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : डीपफेक पर अंकुश लगाने के मकसद से शिवसेना के नेता श्रीकांत शिंदे ने शुक्रवार को लोकसभा में इसे रेगुलेट करने का प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें डीपफेक में चित्रित व्यक्तियों से पूर्व सहमति लेना अनिवार्य किया गया है।

शिंदे ने कहा– "डीपफेक का इस्तेमाल कर उत्पीड़न, धोखाधड़ी और फेक न्यूज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते डीपफेक को रेगुलेट करने की तत्काल आवश्यकता है।" विधेयक में उन अपराधियों के लिए दंड और सजा का भी प्रविधान है जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से डीपफेक का निर्माण या प्रसार करते हैं।

शिंदे ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों पर कहा– " आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और डीप लर्निंग का इस्तेमाल शिक्षा, मनोरंजन और रचनात्मक क्षेत्र में लाभकारी है मगर प्रगति के साथ डीपफेक तकनीक मीडिया मैनिप्यूलेशन के लिए एक महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में उभरी है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारत में डीपफेक के निर्माण, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक

- विधेयक का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- विधेयक में दोषियों के लिए दंड और सजा का भी प्रविधान

प्रतीकात्मक

स्पष्ट कानून बनाना है। इसमें डीपफेक टास्क फोर्स की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जो शैक्षणिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ मिलकर हेरफेर की गई सामग्री का पता लगाने में मदद करेगा। इस बिल में एडवांस्ड इमेज मैनिपुलेशन का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की पहलों का समर्थन करने को एक कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इससे पहले भी कई हस्तियों ने डीपफेक के दुष्प्रभावों पर चिंता जताई है।

एयरलाइंस की मनमानी पर हमेशा के लिए लगाम की तैयारी

कार्रवाई की तैयारी ▶ इंडिगो पर लग सकता है भारी जुर्माना, हटाए जा सकते हैं इसके सीईओ

पीएम ने उड्डयन मंत्रालय को इस मामले में सख्ती से निपटने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मनमानी और दबाव की रणनीति में जिस तरह यात्री बेहाल हुए और उड्डयन नियामक डीजीसीए भी यात्रियों की सुरक्षा को किनारे रखते हुए झुकने को मजबूर हुआ, उससे सरकार को झटका भी लगा है और वह क्षुब्ध भी है। ऐसे में एक तरफ जहां इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है, वहीं हमेशा के लिए एयरलाइंस को लेकर सख्त निगरानी व्यवस्था भी लागू करने की कोशिश है। इसमें किराये को लेकर मनमानी पर भी हर उचित अवसर पर कदम उठाया जा सकता है। बताया जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उड्डयन मंत्रालय को इस मामले में सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मंत्री राममोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत कराया है। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विमानन कंपनियां यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को नजरअंदाज न करें। जाहिर तौर पर यह संदेश है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) फिलहाल भले ही वापस हो गया हो, लेकिन इंडिगो को भी इसे मानना ही पड़ेगा।

सूत्रों के अनुसार, जांच के लिए बनाई गई चार सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसमें इंडिगो पर भारी जुर्माना समेत अन्य कदम शामिल हो सकते हैं। इंडिगो से कुछ रूट पर विमान कम भी कराए जा सकते हैं। जरूरी हुई तो कुछ रूट वापस भी लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार इंडिगो के सीईओ को हटाने के लिए कह सकती है। यह संदेश होगा कि देश किसी कंपनी के दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उससे पहले सरकार की प्राथमिकता है कि अगले दो तीन दिनों में इंडिगो के सभी उड़ान सामान्य किए जाएं। हालांकि इंडिगो अब भी कम से कम एक सप्ताह का समय ले रहा है।

सूत्रों का कहना है कि एयरलाइंस के लिए जो वैश्विक स्थिति है, उसमें किराये पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। लेकिन, समय-समय पर जिस तरह विमानन कंपनियां अनुचित फायदा उठाती हैं, उसके लिए कुछ दिशा-निर्देश बनाए जा सकते हैं।

कोरोना के समय सरकार ने किराया तय कर दिया था। इस वक्त भी तय किया गया है। बड़े पर्व त्योहार के वक्त

इंडिगो की उड़ान रद होने के बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों ने एयरलाइंस स्टाफ पर गुस्सा उतारा। प्रेट

के लिए भी कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। लेकिन, वह निगरानी तंत्र को मजबूत करने से होगा। डीजीसीए को भी निर्देश दिया गया है कि वह निगरानी व्यवस्था नियमित करे और उच्च स्तर पर उसकी रिपोर्टिंग भी करे। इस मामले से निपटते ही डीजीसीए को आने वाले दिनों में कोहरे के कारण बड़ी संख्या में प्रभावित होने वाली उड़ानों के लिए भी व्यवस्था बनाने को कहा गया है।

नाराज 87% विमान यात्री चाहते हैं कार्रवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र: इंडिगो एयरलाइंस के लगातार उड़ानें रद करने और खराब सेवा को लेकर देशभर के यात्रियों में भारी नाराजगी है। बीते चार दिनों में एयरलाइन ने सैकड़ों उड़ानें रद कर दी हैं, जिससे हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। इसका सीधा असर विमान किरायों पर पड़ा है, जो कई रूटों पर बेतहाशा बढ़ गए हैं। प्रभावित यात्रियों का कहना है कि इंडिगो पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी अराजकता दोबारा न हो।'लोकल सर्कल्स' के सर्वेक्षण में शामिल 32,547 यात्रियों में से 87% ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंडिगो के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के 'क्लास एक्शन' प्रविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। केवल 3% ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, जबकि 10% अपने उत्तर को लेकर अनिश्चित रहे। सर्वे में यात्रियों से पूछा गया था कि क्या सैंसीपीए को इंडिगो की सेवा कमी के खिलाफ सामूहिक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लोकल सर्कल्स ने देशभर के 303 जिलों में सर्वेक्षण अभियान चलाया।

रिफंड में भी कोताही की शिकायतें : सर्वे में रद उड़ानों और देरी के साथ-साथ रिफंड न मिलने की शिकायतें सबसे अधिक थीं। यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन ने "100% रिफंड" का वादा किया था, लेकिन अधिकांश मामलों में पूरा पैसा वापस नहीं किया गया। जिन लोगों ने स्वयं टिकट रद किए या रद्दीकरण स्वीकार किया, उन्हें भी पूर्ण भुगतान नहीं मिला। बता दें, 'क्लास एक्शन' में एक समान शिकायत वाले लोगों के समूह की तरफ से आरोपित कंपनी पर कुप्रबंधन या धोखाधड़ी जैसे कृत्यों के लिए सामूहिक रूप से मुकदमा किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे कई उदाहरण हैं- जैसे 2023 में अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस, 2022 में साउथवेस्ट एयरलाइंस और 2020 में कोरोना काल के दौरान अमेरिकन एयरलाइंस पर बड़े पैमाने पर क्लास एक्शन याचिकाएं दायर की गई थीं।

- **लोकल सर्कल्स के सर्वे में 32547 विमान यात्रियों ने दी प्रतिक्रिया**
- **रिफंड पालिसी से भी लोगों में नाराजगी, कहा- पूरे पैसे वापस नहीं किए**

सर्वे के आंकड़े

- 28315 विमान यात्री चाहते हैं इंडिगो पर कार्रवाई
- 3254 लोगों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया
- 976 विमान यात्रियों ने कहा, कार्रवाई की जरूरत नहीं

मनमानी की शर्मनाक कहानी

संजय गुप्त

यह ठीक नहीं कि कोई कंपनी बाजार में अपनी अधिक हिस्सेदारी के सहारे मनमानी करे और यहां तक कि नियामक संस्था को एक जरूरी फैसला लागू करने में अक्षम कर दे

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने भारतीय यात्रियों को पिछले एक सप्ताह में जितना अधिक परेशान किया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इंडिगो के यात्रियों को इसलिए परेशान होना पड़ा, क्योंकि उसने सुरक्षित विमान यात्रा के लिए नागरिक विमानों के संचालन की नियामक संस्था डीजीसीए के नए नियमों का पालन करने की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। ये नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत बनाए गए थे और सभी एयरलाइंस को उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पायलट एक निश्चित समय से अधिक ड्यूटी न करें। सुरक्षित विमान यात्रा के लिए आवश्यक होता है कि पायलट लंबी ड्यूटी के चलते थकान का शिकार न हों।

पायलटों की थकान से बचाने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए जहां एअर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयरलाइन ने पर्याप्त व्यवस्था की, वहीं इंडिगो ने ऐसा कुछ करना आवश्यक नहीं समझा और वह भी तब, जब नए नियम लागू करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी। इससे यही पता चलता है कि इंडिगो नए नियम लागू करने के लिए तैयार ही नहीं थी। डीजीसीए को इसकी निगरानी करनी चाहिए थी कि इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस नए नियमों का पालन करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर रही हैं या नहीं? उसे इंडिगो पर इसलिए अधिक निगाह रखनी चाहिए थी, क्योंकि वह घरेलू विमान सेवा की सबसे बड़ी एयरलाइन है और उसकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है।

जहां डीजीसीए ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया, वहीं इंडिगो ने भी उसे यह सूचित करना आवश्यक नहीं समझा कि वह नए नियमों का पालन करने की स्थिति में नहीं है या फिर उसे पायलट और अन्य कर्मचारी भर्ती करने के लिए कुछ और मोहलत दी जाए। चूंकि डीजीसीए ने सजगता नहीं बरती, इसलिए जब 1 दिसंबर से नए नियम लागू हुए तो इंडिगो की उड़ानें या तो रद होने लगीं या फिर विलंब से चलने लगीं। चूंकि रद और विलंब से चलने वाली उड़ानों की संख्या सैकड़ों में पहुंचने लगी, इसलिए परेशान होने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी। बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद होने से हवाई किराया भी महंगा होने लगा। हजारों विमान यात्री केवल समय पर अपने गंतव्य तक ही नहीं पहुंच सके, बल्कि उन्हें अतिरिक्त किराया भी देना पड़ा। इसका केवल आकलन ही नहीं किया जाना चाहिए कि डीजीसीए और इंडिगो की ढिलाई के कारण लोगों के समय और धन की कितनी बर्बादी हुई, बल्कि उसका भुगतान भी किया जाना चाहिए। इसके लिए किसी को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि इंडिगो केवल खेद जताकर कर्तव्य की इतिश्री कर ले। यदि उसे यात्रियों के समय और धन की बर्बादी की भरपाई के लिए विवश नहीं किया गया तो उसका रवैया सुधरना कठिन ही है।

आलोक त्रिपाठी

इंडिगो को किसी न किसी स्तर पर दंड का भागीदार इसलिए भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसने एक तरह से जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा और साथ ही डीजीसीए को नए नियम लागू करने के अपने ऐसे फैसले को वापस लेना पड़ा, जो विमान यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। डीजीसीए को इसका आभास होना चाहिए कि एक नियामक संस्था के रूप में उसकी क्षमता और साख पर गंभीर सवाल उठे हैं।

भारतीय विमानन बाजार इस समय विश्व का तीसरे नंबर का बड़ा बाजार है। विमान यात्री इंडिगो और एअर इंडिया पर ही अधिक निर्भर हैं। यह साफ दिखा कि इंडिगो ने डीजीसीए को दबाव में लेने की रणनीति पर काम किया और जानबूझकर जरूरत से ज्यादा उड़ानें रद कीं। इसका कारण अपने मुनाफे की अधिक चिंता करना ही रहा होगा। निःसंदेह हर कंपनी को अपने मुनाफे की चिंता करने का अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई कंपनी बाजार में अपने एकाधिकार वाली स्थिति का बेजा लाभ उठाकर नियामक संस्था के उन नियम-कानूनों का भी पालन न करे, जो लोगों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं।

इंडिगो चाहती तो डीजीसीए के नए नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक पायलट और कर्मचारी आसानी से भर्ती कर सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने यह मान लिया कि डीजीसीए उस पर एक सीमा से अधिक दबाव नहीं डाल पाएगा। सच जो भी हो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि डीजीसीए को नए नियमों पर अमल को दो माह के लिए टालना पड़ा है। इससे देश-दुनिया को यही संदेश जाएगा कि भारत सुरक्षित विमान संचालन के प्रति सतर्क नहीं।

इंडिगो के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह पहले भी यात्रियों की सुख-सुविधा का ध्यान न रखने के लिए जानी जाती रही है। इंडिगो से यात्रा करने वालों को यह शिकायत रहती है कि उसके संचालक दल के सदस्य उनसे रूखा व्यवहार करते हैं और वैसी कोई रियायत नहीं देते, जैसी अन्य एयरलाइंस दे देती हैं। इन शिकायतों के बाद भी विमान यात्री इंडिगो से यात्रा करना इसलिए पसंद करते थे, क्योंकि उनका परिचालन समय पर होता था। इसी के चलते एविएशन बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी बढ़ती गई, लेकिन यही बढ़ी हुई हिस्सेदारी अब एक समस्या के रूप में उभर आई। डीजीसीए कुछ भी दावा करे, इंडिगो ने नए नियमों को लागू करने के बजाय अपनी उड़ानों को स्थगित करके केवल लोगों को परेशान ही नहीं किया, बल्कि एक तरह से उसे झुकने के लिए भी बाध्य किया। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं कि कोई कंपनी बाजार में अपनी अधिक हिस्सेदारी के सहारे मनमानी करे और नियामक संस्था को एक जरूरी फैसला लागू करने में अक्षम कर दे।

भले ही नागरिक उड्डयन मंत्री यह कह रहे हों कि सुरक्षा से समझौता किए बिना विमान संचालन संबंधी नए नियमों को स्थगित करने का फैसला किया गया है, लेकिन तथ्य यही है कि पायलटों को कम आराम के साथ विमानों का संचालन करना पड़ेगा। इंडिगो के रवैये के कारण जो संकट खड़ा हुआ, उससे सरकार को सबक लेना होगा और देखना होगा कि नए विमान खरीद रहीं एयरलाइन को विमान संचालन की अनुमति तभी मिले, जब वे नियमों का पालन करने में सक्षम दिखें।

response@jagran.com

मोदी और पुतिन शिखर वार्ता रणनीतिक संतुलन का दमदार प्रदर्शन

वाशिंगटन, आइएएनएस : शीर्ष अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने पीएम नरेन्द्र मोदी व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच नई दिल्ली में हुई शिखर वार्ता को भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की प्रभावशाली मिसाल बताया है। रिपोर्टों में कहा गया कि ऊर्जा सुरक्षा, वाशिंगटन का भू-राजनीतिक दबाव और दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री इस यात्रा और वार्ता के मूल आधार रहे।

'द वाल स्ट्रीट जर्नल' ने उल्लेख किया कि मुलाकात ऐसे समय हुई जब अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर भारत पर द्वितीयक प्रतिबंधों का दबाव बढ़ा रखा है। अखबार ने लिखा कि 2022 से भारत- रूस ऊर्जा साझेदारी दोनों देशों के संबंधों का अहम स्तंभ रही है, और दबावों के बावजूद दोनों देश इसे जारी रखने के संकेत दे रहे हैं। पुतिन ने ईंधन की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया, जबकि मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती बताया।

'द वाशिंगटन पोस्ट' ने इस शिखर सम्मेलन को भारत की विदेश नीति का निर्णायक क्षण बताते हुए कहा,इसने अमेरिका के यूक्रेन शांति दबाव के बीच नई दिल्ली की संतुलनकारी क्षमता को परखा। रिपोर्ट में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डालर तक ले जाने की साझा आर्थिक योजना को भी रेखांकित किया गया।

'द न्यूयार्क टाइम्स' ने भारत- रूस संबंधों को ''ध्रुव तारे जैसा स्थिर'' बताते हुए मोदी-पुतिन के व्यक्तिगत संबंधों की गहराई पर जोर दिया। अखबार ने कहा कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पूरे शिखर सम्मेलन में स्पष्ट रूप से सामने आई। टाइम्स ने पीएम मोदी द्वारा पुतिन का हवाई अड्डे पर प्रोटोकाल तोड़कर स्वागत करने को भी महत्वपूर्ण प्रतीक बताया।

- **अमेरिकी मीडिया ने पश्चिमी दवाव के बीच दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री को अद्भुत बताया**
- **भारत की कूटनीति की परीक्षा- पश्चिम से साझेदारी बरकरार, रूस से रिश्ते अटूट**

दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम नरेन्द्र मोदी। ज्ञात हो, पुतिन चार नवंबर को दो दिनों दौरे पर भारत आए थे। फाइल >>

रूस को वैश्विक मंच से अलग-थलग नहीं किया जा सकता : माइकल कुगेलमैन

दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन ने कहा कि 23वें भारत- रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने पश्चिम को साफ संदेश दिया है कि रूस को वैश्विक मंच से अलग-थलग करना असंभव है। उनके अनुसार, भारत और चीन दोनों ही रूस के साथ गहरे संबंध बनाए रखेंगे, जबकि भारत पश्चिम- विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ- के साथ भी साझेदारी आगे बढ़ाता रहेगा। वहीं, चीन और पाकिस्तान की अति महत्वाकांक्षाओं के बीच भारत को क्षेत्रीय संतुलन के लिए भी रूस की जरूरत है। समाचार एजेंसी एएनआइ से बातचीत में कुगेलमैन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत को ऊर्जा संबंधों के प्रबंधन में बेहद सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा पुतिन का व्यक्तिगत स्वागत और साथ सफर करना यह दर्शाता है कि भारत के लिए रूस से गर्मजोशी भरे संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं।

ट्रंप को भारत से माफी मांगनी चाहिए

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय 'पेंटागन' के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पुतिन के भारत दौरे को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'घोर अक्षमता' करार दिया है। उन्होंने हालिया सर्वेक्षणों के हवाले से कहा कि 65 प्रतिशत लोग ट्रंप को नापसंद करते हैं। समाचार एजेंसी एएनआइ से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी और पुतिन ने ट्रंप का दंभ तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिक खुद ट्रंप की हरकतों पर भड़के हुए हैं, जिन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को खराब कर डाला है। रूबिन ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए उन्हें भारत से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही रूबिन ने सवाल भी किया कि क्या पाकिस्तान की चाटुकारिता या रिश्वतखोरी के जवाब में अमेरिका ने भारत से संबंध खराब किए। उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये कदम अमेरिका को दशकों तक प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से संबंध बेहतर करने का कोई रणनीतिक तर्क नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये विचित्र है कि पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक देश घोषित करने की बजाय ट्रंप मुनीर से गलबहियां कर रहे हैं।

मौजूदा समय में मोदी सबसे प्रभावशाली नेता : मैरी मिलबेन

वाशिंगटन, आइएएनएस : अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने पीएम नरेन्द्र मोदी को भू-राजनीति में इस समय सबसे प्रभावशाली व अहम नेता बताया। उन्होंने पुतिन के साथ नई दिल्ली में हुई शिखर वार्ता के उनके संचालन की प्रशंसा की और वाशिंगटन से भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का आग्रह किया।

मिलबेन ने कहा, मोदी-पुतिन की वार्ता दोनों देशों के बीच गहरे गठबंधन को दर्शाती है। इसे भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह अमेरिका व भारत के बीच गहरी जड़ों और गठबंधन के संदर्भ में भी समान है। उन्होंने कहा, ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे संवेदनशील मामलों पर मोदी ने बेहद रणनीतिक सूझबूझ दिखाई। पुतिन की प्राथमिकता तेल व रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना था, जबकि मोदी ने हर मुद्दे पर राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर बात की। मोदी के कद ने उन्हें आज वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है।

राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम संग घनिष्ठ संबंध रखने वाली मिलबेन ने नई दिल्ली के प्रति ट्रंप प्रशासन के हालिया रुख की आलोचना की। कहा,व्यापार के मामले में भारत के प्रति रवैया बहुत आक्रामक रहा। यहां तक कि धमकाने वाला रवैया अपनाया गया। भारत हमारा मित्र है,सबसे पुराना व मजबूत लोकतांत्रिक साझेदार है। ट्रंप को मोदी को वाशिंगटन यात्रा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। साथ बैठें, माफी मांगें व रिश्ते सुधारें। ऐसा कदम अमेरिकी हितों को मजबूत करेगा, खासकर रूस-यूक्रेन शांति प्रयासों के लिए। मोदी एकमात्र नेता हैं जो वास्तव में मध्यस्थ बन सकते हैं।

- **कहा, मोदी अकेले नेता जो रूस व यूक्रेन शांति प्रयासों में मध्यस्थ बन सकते हैं**
- **ट्रंप को सलाह, मोदी को वाशिंगटन बुलाएं और माफी मांगकर रिश्ते सुधारें**

मैरी मिलबेन।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर भड़का संघर्ष

दोनों के बीच चमन सीमा पर गोलीबारी, पांच के मरने और कई अन्य के घायल होने की खबर

इस्लामाबाद और काबुल ने एक-दूसरे पर लगाए संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप

इस्लामाबाद, रायटर : पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के बीच चमन सीमा पर भारी गोलीबारी की सूचना है। इस संघर्ष में पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। चमन सीमा क्रासिंग, जिसे मैत्री द्वार के नाम से भी जाना जाता है, बलूचिस्तान प्रांत को अफगानिस्तान के कंधार से जोड़ती है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर शुक्रवार देर रात संघर्ष को भड़काने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि अफगान बलों ने बदानी इलाके में मोर्टार दागे थे, जबकि अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि स्पिन बोल्डक पर हमला पाकिस्तान ने किया था।

कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक के सीमावर्ती जिले में एक रिहायशी इलाके के खेत में शनिवार को तालिबानी सुरक्षाकर्मी एक बिना फटे मोर्टार शैल का मुआयना करते। एएफपी

संघर्ष की शुरुआत दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के नए दौर के लगभग एक हफ्ते बाद हुई, जो बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई। हालांकि दोनों पक्ष युद्धविराम जारी रखने पर सहमत हुए थे। पिछले सप्ताहांत सऊदी अरब में हुई वार्ता, अक्टूबर में हुई घातक सीमा झड़पों के बाद तनाव कम करने के लिए कतर, तुर्किये व सऊदी अरब द्वारा आयोजित बैठकों की शृंखला में नवीनतम थी। प्रेट्र के अनुसार, चमन-कंधार राजमार्ग पर भी लड़ाई की खबरें हैं, पर इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। क्वेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी रात 10 बजे शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। चमन जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि एक महिला समेत तीन घायलों को अस्पताल लाया गया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा और विदेश कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

यूक्रेन पर रूस का बड़ा हवाई हमला, कई शहर बने निशाना

- कीव में तीन समेत कुल आठ लोग हुए घायल
- यूक्रेन के बिजलीघरों को बनाया गया निशाना

रूसी हमले के बीच शनिवार को कीव क्षेत्र के फास्टिव शहर में क्षतिग्रस्त रेलवे स्टेशन की इमारत के पास से गुजरते यूक्रेनी बचावकर्मी। एएफपी >>

कीव, एपी : यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए जारी कूटनीतिक प्रयासों के बीच रूस ने शुक्रवार-शनिवार रात यूक्रेनी शहरों पर बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में रूस ने 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों का इस्तेमाल किया लेकिन यूक्रेन ने ज्यादातर को आकाश में ही नष्ट करने का दावा किया है। इन हमलों में यूक्रेन के शहरों में आठ लोग घायल हुए, इनमें से तीन राजधानी कीव में घायल हुए हैं।

रूसी हमलों की चपेट में यूक्रेन के कई बिजलीघर और उनसे जुड़े उपकरण आए हैं। इसके कारण जपोरीजिया के परमाणु बिजलीघर की बिजली आपूर्ति एक बार फिर भंग हो गई है। यह परमाणु बिजलीघर मार्च 2022 में रूस के कब्जे में है जबकि इसके बंद पड़े रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए बिजली की आपूर्ति यूक्रेन से होती है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि आमजनों को ठंड में परेशान करने के लिए रूस यूक्रेनी बिजलीघरों को निशाना बना रहा है। इस बीच यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के रियाजान तेलशोधक कारखाने के निशाना बनने की सूचना है। हमले से कारखाने में आग लग गई है जिसकी लपटें दूर से देखी जा सकती हैं। इस हमले में हुए नुकसान की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। करीब चार वर्षों से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा में शुक्रवार को दूसरे दिन भी अमेरिका और यूक्रेन के वार्ताकारों के बीच वार्ता हुई। जानकारी मिली है कि अब मियामी में वार्ता होगी।

भारत ने द. अफ्रीका को तीसरे वनडे में नौ विकेट से हराया | सीरीज पर 2-1 से कब्जा | यशस्वी जायसवाल ने जड़ा शतक

भारत की 'यशस्वी' जीत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-2 की करारी हार झेलने के बाद भारतीय टीम ने आखिरकार दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मजबूत वापसी करते हुए हिसाब बराबर कर लिया। यशस्वी जायसवाल के शानदार शतक और रोहित शर्मा व विराट कोहली की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने निर्णायक व तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर 'यशस्वी' जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। वह इस सीरीज में पहली बार था जब दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की। हालांकि, मेहमान टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 47.5 ओवर में 270 रन पर सिमट गई। 271 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 39.5 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

यशस्वी-रोहित ने की मजबूत शुरुआत: लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही मजबूत पकड़ बना ली। यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 116 रन की बेहतरीन शतकीय पारी खेली, जो वनडे क्रिकेट में उनका पहला शतक है। रोहित शर्मा ने 75 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि विराट कोहली 65 रन बनाकर नाबाद लौटे। यशस्वी और रोहित ने पहले विकेट के लिए 155 गेंदों पर 155 रन जोड़कर भारत की जीत की नींव रखी। 26वें ओवर में केशव महाराज ने रोहित को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिलाई। उसके बाद यशस्वी और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 84 गेंदों में नाबाद 116 रन की साझेदारी कर भारत को 39.5 ओवर में जीत दिला दी। शानदार प्रदर्शन के लिए यशस्वी को प्लेयर आफ द मैच चुना गया।

20000 से ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय	
रन	खिलाड़ी
34357	सचिन तेंदुलकर
27965*	विराट कोहली
24208	राहुल द्रविड़
20048*	रोहित शर्मा

तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारतीय
- सुरेश रैना
- रोहित शर्मा
- केएल राहुल
- विराट कोहली
- शुभमन गिल
- यशस्वी जायसवाल

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा शतक

शतक	टीम	बनाम	साल
7	द. अफ्रीका	जिंबाब्वे	2010
6	जिंबाब्वे	न्यूजीलैंड	2011
6	पाकिस्तान	आस्ट्रेलिया	2022
6	भारत	द.अफ्रीका	2025

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के

छक्के	टीम	बनाम	साल
70	भारत	इंग्लैंड	2021
63	वेस्टइंडीज	बांग्लादेश	2024
63	भारत	द. अफ्रीका	2025
58	भारत	न्यूजीलैंड	2023
58	द. अफ्रीका	इंग्लैंड	2023

शतक जड़ने के बाद जश्न मनाते यशस्वी • एपी

वनडे सीरीज में कोहली के नाम सबसे ज्यादा रन: प्लेयर आफ द सीरीज चुने गए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 302 रन बनाए। वह सीरीज में 300 से अधिक रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी रहे। दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीट्जके 164 रन के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि 156 रन के साथ यशस्वी तीसरे, 146 रन के साथ रोहित चौथे और 126 रन के साथ केएल राहुल पांचवें स्थान पर रहे।

डिकाक ने खेली शतकीय पारी: डिकाक ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए अपनी क्लास का परिचय दिया। उन्होंने 89 गेंदों में आठ चौके और छह छक्के जमाते हुए 106 रन बनाए। यह वनडे प्रारूप में उनका 23वां शतक और भारत के विरुद्ध सातवां शतक है। हालांकि सीरीज के पहले दो मुकाबलों में डिकाक पूरी तरह असफल रहे थे। डिकाक पहले मैच में खाता नहीं खोल पाए थे, जबकि दूसरे में मात्र सिर्फ आठ रन जोड़ सके। लेकिन निर्णायक मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी की और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

बावुमा के नाम एक और रिकार्ड: कप्तान तेंबा बावुमा एक बार फिर अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने इस मुकाबले में 48 रन की उपयोगी पारी खेलकर 2000 वनडे रन पूरे कर लिए। इस तरह वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दक्षिण अफ्रीका के 22वें बल्लेबाज बन गए। बावुमा का रवींद्र जडेजा की गेंद पर विराट कोहली ने कैच पकड़ा। उनके आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी फिर संभल नहीं सकी और कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सका। मैथ्यू ब्रीट्जके ने 24 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 रन जोड़े, लेकिन दोनों बड़ी पारी खेलने से चूक गए।

कुलदीप-प्रसिद्ध के सामने नहीं चला बल्ला: भारतीय गेंदबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज असहाय नजर आए। कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने 10 ओवर में एक मेडन सहित मात्र 41 रन देकर चार विकेट झटके। उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने पेस और उछाल का शानदार मिश्रण दिखाते हुए 9.5 ओवर में 66 रन देकर चार विकेट हासिल किए। इनके अलावा अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा को भी एक-एक विकेट मिला, जबकि हर्षित राणा और तिलक वर्मा को सफलता नहीं मिल सकी।

स्कोर बोर्ड

प्लेयर आफ द मैच: यशस्वी

प्लेयर आफ द सीरीज: विराट

दक्षिण अफ्रीका : 270 (47.5 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
डी काक बो. प्रसिद्ध	106	89	8/6
रिकल्टन का. राहुल बो. अर्शदीप	0	4	0/0
बावुमा का. कोहली बो. जडेजा	48	67	5/0
ब्रिट्जके एलबीडब्ल्यू प्रसिद्ध	24	23	0/2
मार्करैम का. कोहली बो. प्रसिद्ध	1	3	0/0
ब्रेविस का. रोहित बो. कुलदीप	29	29	2/1
जैनसेन का. जडेजा बो. कुलदीप	17	15	2/0
बाश का. एंड बो. कुलदीप	9	12	0/0
महाराज अविजित	20	29	2/0
नगिदी एलबीडब्ल्यू कुलदीप	1	10	0/0
बर्टमैन बो. प्रसिद्ध	3	7	0/0

अतिरिक्त : 12, विकेट : 1-1 (रिकल्टन, 0.5), 2-114 (बावुमा, 20.6), 3-168 (ब्रिट्जके, 28.2), 4-170 (मार्करैम, 28.6), 5-199 (डी काक, 32.5), 6-234 (ब्रेविस, 38.1), 7-235 (जैनसेन, 38.3), 8-252 (बाश, 42.3), 9-258 (नगिदी, 44.4)। गेंदबाजी : अर्शदीप 8-1-36-1, हर्षित 8-2-44-0, प्रसिद्ध 9.5-0-66-4, जडेजा 9-0-50-1, कुलदीप 10-1-41-4, तिलक 3-0-29-0

भारत : 271/1 (39.5 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
जायसवाल अविजित	116	121	12/2
रोहित का. ब्रिट्जके बो. महाराज	75	73	7/3
विराट कोहली अविजित	65	45	6/3

अतिरिक्त : 15 (लेग : 2, वा : 13)

विकेट पतन : 1-155 (रोहित, 25.5), गेंदबाजी : जैनसेन 8-1-39-0, नगिदी 6.5-0-56-0, महाराज 10-0-44-1, बर्टमैन 7-0-60-0, बाश 6-0-53-0, मार्करैम 2-0-17-0

आखिरकार जीता टास

भारतीय टीम ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टास जीत लिया। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टास जीता। भारत को यह टास जीत लगातार 20 वनडे मैचों में हार के बाद मिली है। इससे पहले भारत ने साल 2023 में अपने घर में खेले गए वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के विरुद्ध टास जीता था। इसी विश्व कप कप के फाइनल मे रोहित टास हारे थे और तब से भारतीय टीम लगातार वनडे में हार रही थी।